MR. CHAIRMAN: Mr. Baishya, please.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Kindly allow me, Sir.

MR. CHAIRMAN: If you want to raise a discussion, please ask for it. We will deal with it.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, when we are discussing this subject. ...*(Interruptions)*... Why can't you allow me, Sir? ...*(Interruptions)*... One question, Sir.

MR. CHAIRMAN: I am afraid, not.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, this is related to the sovereignty...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... You are simply denying your colleagues the right to deal with the next question. Why do you want to do it? ...*(Interruptions)*... I am afraid, I cannot violate the rule of three supplementaries.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: I would like to say only one thing, Sir. ...*(Interruptions)*... This is related to Assam. This is related to the sovereignty of our country. I want to just ask...

MR. CHAIRMAN: I don't think you are making the point fairly. Please do not interrupt Question Hour. I request you. If you want a discussion on the subject, ...*(Interruptions)*...

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, in the last Winter Session, the hon. Home Minister...

MR. CHAIRMAN: I am afraid, I will not take that question and will not request the Minister to answer it.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, I want to know...

MR. CHAIRMAN: Please.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: What steps have been taken by the Government...

MR. CHAIRMAN: I am afraid this question will not be answered. Question No. 123

वस्त्र-उद्योग में पूंजी-निवेश

*123. **श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा**:
श्री शिवानन्द तिवारी:††

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2004 से 2008 तक की अवधि के दौरान, देश में वस्त्र-उद्योग में अत्यधिक पूंजी-निवेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004 तथा वर्ष 2008 के अंत तक वस्त्र-उद्योग में कितनी-कितनी पूंजी का निवेश किया गया था;

---

††सभा में यह प्रश्न श्री शिवानन्द तिवारी द्वारा पूछा गया ।

(ग) वर्ष 2004 तथा 2008 में इस पूंजी निवेश में से कपड़ा मिलों, विद्युत-चालित करघा, हथकरघा तथा सिले-सिलाए वस्त्रों के क्षेत्र में क्रमशः कितना-कितना पूंजी-निवेश किया गया था; और

(घ) प्रत्येक क्षेत्र में औसतन कितन-कितने रुपये का वार्षिक कारोबार हुआ है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारतीय वस्त्र उद्योग नई चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से अपनी उत्पादन प्रौद्योगिकी के उन्नयन और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए प्रबल प्रयास कर रहा है। वस्त्र क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने वर्ष 1999 में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की है। वर्ष 2004-05 से 2008 (सितम्बर) के दौरान टीयूएफएस के तहत स्वीकृत कुल परियोजना लागत 120916.13 करोड़ रु. (अनुमानित 20% सीएलसीएस/15% एमएमएस सहित) थी। 2004-05 में टीयूएफएस के तहत परियोजना स्वीकृत लागत 7409 करोड़ रुपए थी और वर्ष 2008-09 (सितम्बर तक) के दौरान 11265.13 करोड़ रु. थी। इसी प्रकार वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने की दृष्टि से इसके आधुनिकीकरण के उद्देश्य से 2005 में एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) शुरू की गई। ये योजनाएं इस तरीके से तैयार की गई हैं ताकि वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए निजी क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित किया जा सके। एसआईटीपी के तहत 2004-05 से 2008-09 तक स्वीकृत कुल परियोजना लागत 4203.15 करोड़ रु. थी जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 1438.03 करोड़ रु. था।

(ग) वर्ष 2004-05 और 2008-09 (सितम्बर तक) में विद्युतकरघों, सिले-सिलाए परिधानों (स्टिच्ड क्लॉथ) और अन्य (वस्त्र मिलों सहित) में टीयूएफएस के तहत स्वीकृत परियोजना लागत नीचे दी गई है:—

टीयूएफएस के तहत स्वीकृत परियोजना लागत

करोड़ रु. में

क्षेत्र	2004-05	2008-09 (सितम्बर तक)
विद्युतकरघा (20% सीएलसीएस/एमएमएस सहित)	128	408.50
सिलेसिलाए परिधान (स्टिच्ड क्लॉथ)	292	300
अन्य (वस्त्र मिलों सहित)	6989	10556.63
कुल	7409	11265.13

(घ) उद्योग के क्षेत्र-वार वार्षिक कारोबार का विवरण उपलब्ध नहीं है, तथापि 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए वस्त्र एवं पटसन उद्योग संबंधी कार्यकारी समूह की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान वस्त्र उद्योग का निर्यात बाजार आकार 47 बिलियन अमरीकी डालर का था और 11वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 2011-12 के अंतिम वर्ष के दौरान इसके 115 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ने का अनुमान है।

औसत कारोबार का अनुमान वर्ष 2007-08 के दौरान उत्पादन तथा ओसत बाजार कीमत के आधार पर लगाया गया है और इस आधार पर अनुमानित औसत कारोबार इस प्रकार है:—

विद्युतकरघा क्षेत्र	=	41294.11 करोड़ रु.
सिलेसिलाए परिधान क्षेत्र	=	105497.69 करोड़ रु.
सूती मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिल	=	56376.57 करोड़ रु.

Capital investment in textile industry

†*123. SHRI RAJ MOHINDER SINGH MAJITHA:
SHRI SHIVANAND TIWARI:††

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been huge capital investment in the textile industry during the period 2004 to 2008 in the country;

(b) if so, the capital invested in the textile industry in 2004 and at the end of 2008;

(c) out of this capital investment, the capital invested in the sectors of textile mills, powerloom, handloom and stitched clothes in 2004 and 2008; and

(d) the average annual turnover in each of the sector?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI SHANKERSINH VAGHELA): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Indian Textiles Industry is making vigorous efforts to upgrade its production technology and improve competitiveness in order to face the new challenges. To encourage investment in the textile sector, Government has launched Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) in the year 1999. The total project cost sanctioned under TUFS during the period 2004-05 upto 2008 (September) was Rs. 120916.03 crores (including estimated 20% CLCS/15% MMS). The project sanctioned cost under TUFS in 2004-05 was Rs. 7409 crores and during the year 2008-09 (upto September) was Rs. 11265.13 crores. Similarly, Scheme for Integrated Textile Park (SITP) launched in 2005, aimed at modernizing the textile industry with a view of making it internationally competitive. These schemes are designed in such a way as to encourage investment by the private sector for modernizing the textile industry. Under SITP, from 2004-05 to 2008-09, the total project cost sanctioned was Rs. 4203.15 crore out of which the share of Government of India (GoI) was Rs. 1438.03 crore.

(c) The project cost sanctioned under TUFS in powerlooms, readymade garments (stitched clothes) and others (including textiles mills) in 2004-05 and 2008-09 (upto September) is given below:—

Project cost sanctioned under TUFS

In Rs. crore

Sector	2004-05	2008-09 (upto September)
1	2	3
Powerloom (incl. estimated 20% CLCS/MMS)	128	408.50

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Shivanand Tiwari.

1	2	3
Readymade garment (Stitched Cloth	292	300
Others (including textile mills)	6989	10556.63
Total	7409	11265.13

(d) The details of sector-wise annual turnover of the industry is not available, however, as per the report of the Working Group on Textile and Jute Industry for the Eleventh Five Year Plan, the export market size of textile industry was US $ 47 billion during the year 2005-06 and is projected to increase to US $ 115 billion during the terminal year of the Eleventh Five Year Plan, *i.e.*, 2011-12.

The average turnover has been estimated on the basis of production and average market price during the year 2007-08 and on this basis, the average turnover is estimated as under:—

Powerloom sector	=	Rs. 41294.11 crore
Readymade Garment sector	=	Rs. 105497.69 crore
Cotton Manmade Fibre Textile Mills	=	Rs. 56376.57 crore

श्री शिवानन्द तिवारी : सभापति महोदय, आज यह वस्त्र उद्योग का क्षेत्र संकट में है और इस कारण हमें किसानों के बाद बुनकरों की आत्म-हत्याओं की खबरें अखबारों में पढ़ने को मिल रही हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि टेक्नोलोजी अपग्रेडेशन स्कीम के तहत 2008-09 के सितंबर महीने तक इन्होंने 11,265 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च किए हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि पावरलूम के क्षेत्र में 408 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए और मिलों तथा अन्य सेक्टर में 10,556 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च किए गए। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि वर्ष 2007-08 में मिल क्षेत्र में महज 1,781 मिलियन वर्ग मीटर कपड़ा तैयार किया गया था, जबकि पावरलूम क्षेत्र में 34,736 मिलियन वर्ग मीटर कपड़ा तैयार हुआ था और हथकरघा के क्षेत्र में 6,947 मिलियन वर्ग मीटर कपड़ा तैयार हुआ था? मंत्री महोदय से मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जो क्षेत्र 1,781 मिलियन वर्ग मीटर कपड़ा तैयार करता है, उसको आप टेक्नोलोजी अपग्रेडेशन के लिए 10,556.63 करोड़ रुपये देते हैं और जो क्षेत्र लगभग सात हजार मिलियन वर्ग मीटर कपड़ा तैयार करता है और 34,736 मिलियन वर्ग मीटर कपड़ा तैयार करता है, उसको आप केवल 408.50 करोड़ रुपये देते हैं, इसका क्या मतलब है? हम आपसे यह जानना चाहते हैं।

श्री शंकर सिंह वाघेला: सभापति महोदय, Technology Upgradation Fund Scheme बड़ी इंडस्ट्रीज, जो मशीन इम्पोर्ट करते हैं, उनके लिए है। मैं समझता हूँ कि 2004 और 2008 में इंडस्ट्री ने इसका काफी लाभ लिया है, जिससे एम्प्लायमेंट भी बढ़ा है। आप जो हैंडलूम की बात करते हैं, वह पावर से नहीं चलता है। एक लूम 8 हजार/10 हजार की होती है।

श्री शिवानन्द तिवारी: मैंने हैंडलूम और पावरलूम, दोनों के बारे में कहा है।

श्री शंकर सिंह वाघेला: पावरलूम के लिए जो भी स्कीम है, उसके तहत वे कई लाभ लेते हैं। लेकिन यह बड़ी स्कीम है, बड़े mill owners इसका उपयोग करते हैं। जो पुरानी मशीनरी इम्पोर्ट होती है, यह स्कीम उसके लिए है। पावरलूम के लिए भी जो सिस्टम है, इसमें लाभ लिया है लेकिन कम लाभ लिया है। लाभ लेना इनके हाथ में है और लाभ देना हमारे हाथ में है। जो प्रपोजल आता है, उसके हिसाब से हम लाभ देते हैं।

श्री शिवानन्द तिवारी: सभापति महोदय, कपड़ा उद्योग क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार हथकरघा और पावरलूम सेक्टर में मिलता है और यही दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा कपड़ा तैयार कर रहे हैं। अगर इनके मुकाबले देखा जाए तो यह जो मिल सेक्टर है, उसमें कपड़े का उत्पादन बहुत ही सीमित है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि आज जब आर्थिक मंदी है और कई उद्योग बंद हो रहे हैं, वैसी हालत में कपड़ा उद्योग के अंदर जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, उसको आप क्यों neglect कर रहे हैं और इस बीच में हैंडलूम और पावरलूम सेक्टर में कितने उद्योग बंद हुए हैं?

श्री शंकर सिंह वाघेला: सभापति महोदय, उद्योग बंद हुए हैं, ऐसा नहीं है। स्लोडाउन जरू र है, लेकिन पावरलूम और हैंडलूम के comparison में spinning mills बड़ी इंडस्ट्रीज़ है और बडी मशीनें इम्पोर्ट करते हैं, इसलिए इनको बड़ा लाभ मिलता है। पावरलूम में छोटी मशीनें होती हैं, इसलिए छोटा लाभ मिलता है, जबकि हैंडलूम में मशीन होती ही नहीं है बल्कि अपना हथकरघा होता है। यह जो स्लोडाउन हो रहा है, वह इंटरनेशनल है जिसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी आ रहा है, लेकिन इसके कारण कोई फैक्टरी बंद हो गई, ऐसा हमारे पास कोई भी official figure नहीं आया है।

श्री शिवानन्द तिवारी: क्या आप इसका सर्वे करा कर कोई figure इकट्ठा करेंगे?

श्री शंकर सिंह वाघेला: वह process में है।

सुश्री सुशीला तिरिया: सर, मंत्री जी ने एक्सपोर्ट के लिए अभी 115 बिलियन का लाभ बताया है। लेकिन उड़ीसा और गुजरात में ऐसे-ऐसे हैंडलूम्स और पावरलूम्स हैं, जिनमें awareness पैदा करने के लिए, जिनको encourage करने के लिए upgradation fund scheme के अलावा भी मंत्री जी ने कोई कदम उठाया है, जिससे awareness हो, जिससे encouragement हो और जिससे आपके विभाग को लाभ मिले?

श्री शंकर सिंह वाघेला: सर, हैंडलूम और पावरलूम के लिए हमारी अलग-अलग स्कीम्स हैं और बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग स्कीम्स हैं। एक्सपोर्ट का सब्जैक्ट पूरी तरह से अलग है। TUFS के अंदर जो भी आता है, उसका जवाब मैंने दे दिया है।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether it has come to the notice of the hon. Minister that the Commerce Secretary, Government of India has given a statement saying that in the near future 15 lakh workers from the textile sector alone are going to be laid off or going to lose their jobs. If so, what are the steps taken by the Government? What is the scheme that has been formulated to safeguard, at least, the people who are already working, forget about the new jobs?

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, 60,000 workers have already lost their jobs in Tirupur, Tamil Nadu.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: So, what are the steps being proposed by the Government to tackle this situation?

श्री शंकर सिंह वाघेला: सर, जब investment बढ़ता है तो employment भी बढ़ता है और जब investment घटता है तो employment भी घटता है। यह international recession है जिसका effect 2008 के half के बाद आना शुरू हुआ है। हमारे पास official figures नहीं हैं, लेकिन लगभग 5 लाख लोगों का unemployment हुआ होगा, टोटल स्लोडाउन है। कॉमर्स मिनिस्ट्री की फिगर्स कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास होगी, लेकिन जो सर्वे कराया गया है, उसके अनुसार जो figures आ रही हैं, यह और भी बढ़ने की संभावना है। मैं समझता हूँ कि वित्त मंत्रालय और PMO की ओर से जो मॉनिटरिंग है, सबको अलग-अलग — कल भी शायद

यह कहा गया है, इससे काफी इंडस्ट्रीज को राहत और लाभ प्राप्त होगा। यह effect अगले मॉनसून तक रहेगा, लेकिन जितना effect वेस्टर्न कंट्रीज पर है, उतना effect इंडिया पर नहीं होगा।

श्री महेन्द्र मोहन: सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर जो टेक्सटाइल मिलों का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है, वहाँ पर उन मिलों की हालत बहुत ही खराब है और वहाँ के सारे मजदूर बेकार बैठे हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय ने वहाँ की टेक्सटाइल मिलों की जमीनों को बेचकर उन मिलों को पुनः प्रारंभ कराने के आश्वासन दिये हैं, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है और टेक्सटाइल मिलें अभी भी बंद पड़ी हुई हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि वहाँ जो बी.आई.सी. एवं अन्य टेक्सटाइल मिलें बंद पड़ी हैं और जिनकी जमीनें भी बेची जा चुकी हैं, उनको वह कब तक चालू कराने की व्यवस्था करा रहे हैं?

श्री शंकर सिंह वाघेला: सर, एनटीसी का सब्जैक्ट अलग है। लेकिन एनटीसी के लिए हमने 22 मिलें मॉडर्न की हैं और उसका performance भी काफी अच्छा है। बाकी 18 मिलें हमने joint venture में शुरू की हैं। जहाँ तक कानपुर के बी.आई.सी. और एल्गिन मिलों का सवाल है, इनके बारे में हमने कैबिनेट को पेपर भेजे हैं। एनटीसी के नीचे ऐसा कोई वर्कर नहीं है जिसे तनख्वाह नहीं मिलती है। अगर मिल बंद भी है तब भी जो टेक्सटाइल वर्कर है, उसे समय पर तनख्वाह मिल जाती है। बीआईसी के लोगों के लिए भी हमने एनटीसी से लोन लेकर तनख्वाह देने का प्रावधान किया था।

Development of leather sector

*124. MS. MABEL REBELLO:††
SHRI B.J. PANDA:

Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government proposes to grant Rs. 913 crore for development of leather sector in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) the status of leather park projects and which are the places where such parks are proposed to be located in the country; and

(d) the action plan under the above project to upgrade the skills of rural artisans?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION, MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ASHWANI KUMAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Central Government has approved eleven sub-schemes for implementation during the Eleventh Five Year Plan period under Indian Leather Development Programme (ILDP). The details of these sub-schemes are as under:—

Sl. No.	Name of the sub-scheme under ILDP	Allocation for Eleventh Five Year Plan (Rs. in crores)
1	2	3
1.	Integrated Development of Leather Sector	253.43

††The question was actually asked on the floor of the House by Ms. Mabel Rebello.